[2024] 10 एस.सी.आर. 1344 : 2024 आईएनएससी 763

शशि भूषण प्रसाद सिंह

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2024 का सिविल अपील सं. 11030)

04 अक्टूबर 2024

[बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा, * न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

अंतिम चयन सूची तैयार होने के बावजूद, जो नियुक्ति प्रक्रिया के समापन का संकेत देती है, राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को रद्द करने और नए नियमों के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। क्या यह खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को प्रभावी रूप से बदलने के बराबर है, जो अस्वीकार्य है और उम्मीदवारों को पिछले नियमों के तहत विचार के उनके वैध अधिकार से वंचित करता है।

हेडनोट्स

बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम, 2015 - बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम 2017 - भर्ती - नियुक्ति प्रक्रिया - बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 08.03.2019 के विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न राज्य विभागों में कनिष्ठ अभियंता के पद पर रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए - यहाँ निजी उत्तरदाताओं के आवेदनों को बीटीएससी द्वारा इस आधार पर अयोग्य पाया गया कि उनके संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा विभाग परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था - रिट याचिकाएं दायर की गईं - उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के बाद, अंतिम चयन सूची 19.12.2022 को तैयार की गई, जिसे सीलबंद लिफाफे में रखा गया और एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर करके अदालत की अनुमति मांगी गई - हालांकि, न्यायालय को यह सूचित किए जाने के बाद कि राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया की समीक्षा पर विचार कर रही है, आवेदन स्थगित कर दिया गया -तत्पश्चात 25.01.2023 को राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन के अंतर्गत

सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने तथा संशोधित नियमों के लिए अनुमोदन आरंभ करने का निर्णय लिया गया:

अभिनिर्धारित कियाः वर्तमान मामले में, अंतिम चयन सूची तैयार करने के बावजूद, जो नियुक्ति प्रक्रिया के समापन का संकेत देती है, राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया को समाप्त करना चाहती है और नए नियमों के तहत एक नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना चाहती है - इस अदालत की सुविचारित राय में, यह खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को प्रभावी ढंग से बदलने के बराबर है जो अस्वीकार्य है और उम्मीदवारों को पिछले नियमों के तहत विचार के उनके वैध अधिकार से वंचित करता है -उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अचानक और बिना कोई कारण बताए और रिट याचिकाओं में शामिल किसी भी मुद्दे पर निर्णय लिए बिना ही उनका निपटारा कर दिया, राज्य के वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज कर लिया और राज्य को विचाराधीन नियमों में संशोधन करने की अनुमति दी - चूंकि, 02.04.2022 को चयन सूची घोषित होने तक पूरी भर्ती प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार संपन्न हुई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से रद्द नहीं किया गया है, और चूंकि एआईसीटीई ने भी अपना रुख जारी रखा है कि निजी संस्थानों के लिए इसकी मंजूरी आवश्यक नहीं है, और चूंकि 19.04.2022 का आदेश (जिसमें पहली चयन सूची आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी) अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए न्याय का हित तभी पूरा होगा जब राज्य/आयोग को 08.03.2019 के विज्ञापन के संबंध में मेधावी उम्मीदवारों की एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए - इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.04.2022 के आदेश के अनुपालन में मेधावी उम्मीदवारों की दिनांक 08.03.2019 के विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों के लिए एक नई चयन सूची तैयार की जाए-नई चयन सूची में वे मेधावी उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो अन्यथा पात्र थे लेकिन केवल नियमों में 2017 के संशोधन के कारण अपात्र घोषित किए गए थे, यानी उनके संस्थान को एआईसीटीई द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने के कारण, और सभी समान रूप से सफल उम्मीदवार। [पैरा 26,27,29]

न्याय दृष्टांत

*भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्न बनामए. आई. सी. टी. ई. और अन्य [2001] पूरक।3 एससीआर 253:**(2001) 8 एस. सी. सी. 676;** पंजाब नेशनल बैंक बनाम अनित कुमार दास [2020] 9 एससीआर 925:**(2021) 12 एस. सी. सी 80;** अध्यक्ष **एस. बी. आई. और ए.***

एन. आर. वी.एम. जे. जेम्स** [2021] 7 एससीआर 373:**(2022) 2 एस. सी. सी. 301;** के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। [2008] 2 एससीआर 1025 **:(2008) 3 एस. सी. सी. 512 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम, 2015; बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सिविल) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम 2017; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून; भर्ती; नियुक्ति; खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों में परिवर्तन; विचार का वैध अधिकार; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद; बिहार तकनीकी सेवा आयोग।

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11030/2024

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.02.2023 के निर्णय एवं आदेश से, सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3411/2022

सहित

सिविल अपील संख्या 11031, 11032, 11033 एवं 11034/2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, डॉ. राजीव धवन, पी. एस. पटवालिया, रंजीत कुमार, रुद्रेश्वर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री मनिका त्रिपाठी, आशुतोष कौशिक, बरुण डे, रॉनी जॉन, वंश कालरा, सुश्री मालविका सिंह, मनोज कुमार श्रीवास्तव, अजमत हयात अमानुल्ला, सुश्री रेबेका मिश्रा, गोपाल सिंह, शिवम सिंह, सुयश व्यास, स्मारहर सिंह, सुश्री श्वेता कुमारी, मनोज कुमार, मो. असीम, पंकज प्रकाश, प्रेम प्रकाश, सुश्री विनीता सिंह, आदित्य हर्ष, सुश्री दीपाली नंदा, यादव नरेंदर सिंह, अनिल सोनी, हरीश पांडे, आदित्य वैभव सिंह, सुश्री वन्या गुप्ता, नीरज शेखर, श्रीमती क्षमा शर्मा, अरविंद गुप्ता, अधिवक्ता - उपस्थित दलों के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

निर्णय सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमुर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलों का वर्तमान समूह पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 3411/2022 (**'सीडब्ल्यूजेसी'**) तथा अन्य संबद्ध मामलों (**'आक्षेपित आदेश'**) में दिनांक 16.02.2023 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ता, जो कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद के लिए दिनांक 08.03.2019 के विज्ञापन के अनुसार आयोजित भर्ती प्रक्रिया में असफल उम्मीदवार थे, ने बिहार राज्य में तकनीकी पद पर चयन/नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित करते हुए दिनांक 07.11.2017 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियमावली 2017 के नियम 9(1)(ii) की वैधता को चुनौती दी थी। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता उक्त भर्ती प्रक्रिया में सफल उम्मीदवार हैं।

3. वर्तमान मामला बिहार तकनीकी सेवा आयोग ('**बीटीएससी**') द्वारा दिनांक 08.03.2019 को विज्ञापन संख्या 01/2019 जारी करने से शुरू होता है, जिसमें विभिन्न राज्य विभागों में कनिष्ठ अभियंता के पद पर 6,379 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे ('**विज्ञापन**')। विज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया था कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:

> *"शैक्षिक योग्यता।*
>
> *क) कनिष्ठ अभियंता (सिविल)*
>
> *i. संबंधित तकनीकी शैक्षिक परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिसे **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद**, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हो।*
>
> *ii. यूजीसी अधिनियम के तहत स्थापित संबंधित डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा गैर-दूरस्थ मोड के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बशर्ते कि डीम्ड विश्वविद्यालय उक्त पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।"*

यह ध्यान देने योग्य है कि यह आवश्यकता बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती नियम, 2015 ('**नियम**'), जो 2017 में संशोधित की गयी, के नियम 9 (1) (iii) से ली गई है और जो की समान है।

4. वर्तमान अपील में निजी प्रतिवादी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे। वे सभी आवेदक थे जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित और अनुमोदित निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों से डिप्लोमा था। उनके आवेदन बीटीएससी द्वारा इस आधार पर अयोग्य पाए गए कि उनके संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ('**एआईसीटीई**') द्वारा अनुमोदित नहीं थे। व्यथित होकर, उन्होंने नियम 9 (1)(iii) को अन्य वैधानिक प्रावधानों और **भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य** 2001(8) एससीसी 676 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ असंगत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के प्रावधानों की व्याख्या पर यह माना गया कि विश्वविद्यालयों को तकनीकी संस्थानों के दायरे से बाहर रखा गया है और इसलिए उन्हें तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने से पहले एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5. रिट याचिकाकर्ताओं ने एआईसीटीई द्वारा सभी केंद्रीय/राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 2022-23 के लिए एआईसीटीई अनुमोदन के बारे में जारी दिनांक 09.02.2022 के सार्वजनिक नोटिस पर भरोसा किया, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:

> *"प्रिय महोदय/महोदया,*
>
> *यह सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में एआईसीटीई अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की है और माना है कि विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा में पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों का नया विभाग शुरू करने के लिए एआईसीटीई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। विश्वविद्यालयों का एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना दायित्व या कर्तव्य है। तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एआईसीटीई विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है, जो एआईसीटीई के प्रासंगिक नियमों/विनियमों के तहत प्रावधानों*

के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी संबद्ध संस्थानों को एआईसीटीई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ केंद्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय कुछ के लिए एआईसीटीई की आंशिक स्वीकृति ले रहे हैं। चयनित तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, जिससे हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

इसलिए, एआईसीटीई ने निर्णय लिया कि हितधारकों के बीच भ्रम से बचने के लिए विश्वविद्यालयों को तकनीकी पाठ्यक्रमों की आंशिक मंजूरी नहीं दी जाएगी।

तदनुसार, सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि या तो वे सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों की पूर्ण स्वीकृति ले लें, या वे एआईसीटीई की मंजूरी के बिना जारी रख सकते हैं।

6. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि रिट याचिकाकर्ताओं के रुख को एआईसीटीई ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुष्ट किया था, जैसा कि उनके दिनांक 12.05.2022 के जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:

"8. अब तक रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 15 में दिए गए बयानों से संबंधित यह प्रस्तुत किया गया है कि एआईसीटीई ने अनुमोदन प्रक्रिया 2021-22 के लिए अपनी सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह बताया था कि केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक निजी विश्वविद्यालयों को ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को छोड़कर तकनीकी कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन प्रक्रिया 2022-23 के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में भी इस स्थिति की पुष्टि की गई है।

7. इस स्तर पर, यह देखना उचित है कि सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3411/2022 दाखिल करने से पहले, उच्च न्यायालय पहले से ही विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया पर लागू नियमों के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई समान रिटों पर सुनवाई कर रहा था। तदनुसार, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9887/2019 में पारित दिनांक 02.05.2019 के आदेश के अनुसार, बीटीएससी को चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामों को कार्यवाही के परिणाम आने तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना था। इस आदेश को बाद में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 21651/2018 में दिनांक 06.12.2019 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया को पूरा करने की

अनुमति दी, लेकिन निर्देश दिया कि नियुक्तियों के सभी आदेशों में यह उल्लेख होना चाहिए कि नियुक्तियां रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन हैं और इसलिए, चयनित उम्मीदवार किसी भी इक्विटी का दावा नहीं कर सकते हैं।

8. तदनुसार, 02.04.2022 को, बीटीएससी ने विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों के लिए अपनी चयन सूची (**'चयन सूची'**) प्रकाशित की और चयनित उम्मीदवारों को विशिष्ट विभागों को आवंटित भी किया गया। उपर्युक्त अंतरिम आदेशों के अनुपालन में, चयन सूची ने न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2019 के आदेश में दिए गए निर्देशों को पुनः प्रस्तुत किया और स्पष्ट रूप से कहा कि लंबित कार्यवाही में अंतिम आदेश के आलोक में चयन सूची प्रभावित होगी।

9. इसके बाद, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7312/2021 के तहत एक अलग अनुरूप रिट कार्यवाही में, दिनांक 19.04.2022 के आदेश के अनुसार, नियमों के नियम 4(ए) को मनमाना और अनुचित पाया गया, जिसके तहत राज्य द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा धारकों को 40% संस्थागत आरक्षण दिया गया था। नतीजतन, नियम 4(ए) के अनुसार तैयार की गई चयन सूची को अलग रखा गया और बीटीएससी को एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य तकनीकी संस्थान बोर्ड, बिहार से संबद्ध और राज्य के भीतर स्थित किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा धारकों को 40% संस्थागत आरक्षण देने वाली एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया।

10. इसके बाद, बीटीएससी ने विज्ञापन के तहत मेरिट सूची को अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7761/2022 में आदेश 01.12.2022 के तहत निर्देश दिया गया कि न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने तक परिणामों की घोषणा को रोक दिया जाए। 19.12.2022 को एक सूची तैयार की गई, उसे सीलबंद कवर में रखा गया और सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7761/2022 (**'अंतिम चयन सूची'**) में एक अंतरिम आवेदन दायर करके न्यायालय की अनुमति मांगी गई। महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद कि राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने पर विचार कर रही है, आवेदन की सुनवाई स्थगित कर दी गई।

11. 25.01.2023 को बिहार सरकार ने नियमावली और विज्ञापन के खिलाफ लंबित कई मुकदमों और इसके परिणामस्वरूप नियुक्तियों में 4 साल की देरी से उत्पन्न कानूनी मुद्दों पर विचार करने के लिए विभिन्न निर्माण विभागों के सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक

बुलाई। अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापन के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने और संशोधित नियमों के लिए अनुमोदन आरंभ करने का निर्णय लिया गया।

12. एक बार जब दिनांक 25.01.2023 का निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया गया, तो राज्य सरकार को दिनांक 25.01.2023 के अपने निर्णयों को लागू करने की अनुमति दी गई और न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में कुछ भी शेष नहीं बचा है। तदनुसार, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3411/2022 और अन्य सभी अनुरूप रिटों का निपटारा निम्नलिखित तरीके से किया गया:

> *"तत्काल रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत/राहत के लिए प्रार्थना की है:*
>
> > *i. अधिसूचना संख्या में निहित नियम 9(1)(ii) "बिहार जल संसाधन विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग (सिविल) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 को रद्द करने के लिए। 3950 दिनांक 07.11.2017 को बिहार राज्य में तकनीकी पद पर चयन/नियुक्ति के लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित करते हुए इसे अन्य वैधानिक प्रावधानों के साथ असंगत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन तथा भारत के संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।*
> >
> > *ii. उक्त नियमों को भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित करने के लिए, जहां तक नियम-9(1)(iii) में संशोधन का संबंध है।*
> >
> > *iii. किसी अन्य राहत/राहत के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार पाया जाता है।*
>
> *2. मामला जूनियर इंजीनियर के पद पर चयन और नियुक्ति से संबंधित है। इस संबंध में, 08.03.2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। समय-समय पर मामले की सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान हमने जूनियर इंजीनियर के पद को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों में कुछ त्रुटियां देखी हैं। अंततः, राज्य सरकार ने 08.03.2019 को जारी विज्ञापन के संदर्भ में जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया है और मौजूदा*

नियमों में कुछ त्रुटियों को सुधारते हुए नए नियम जारी करने या संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में, अनुपूरक जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-ए के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से 25.01.2023 के निर्णय को संलग्न करते हुए अनुपूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियमों में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, जिन्हें संबंधित नियमों आदि में संशोधन करते समय ठीक किया जाएगा। राज्य प्रतिवादियों की प्रस्तावित कार्रवाई इस प्रकार है:

'4. सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि:

क. वर्तमान में उत्पन्न कानूनी उलझनों के मद्देनजर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित विज्ञापन संख्या 01/2019 से होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाए।

ख. जो विभाग पूर्व में आयोग को नियुक्ति हेतु अपनी अधियाचना भेज चुके हैं, वे बिहार तकनीकी सेवा आयोग से अपनी अधियाचना वापस ले लेंगे तथा ऐसे विभाग नई भर्ती नियमावली बनने के बाद ही नए सिरे से अपनी अधियाचना भेजेंगे।

ग. विभिन्न विभागों में वर्तमान में प्रचलित कनीय अभियंता नियुक्ति नियमावली को रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की जाए तथा उसके बाद संशोधित कनीय अभियंता नियुक्ति नियमावली बनाई जाए।

घ. कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति के लिए संशोधित कनिष्ठ अभियंता भर्ती नियमों को मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं।'

3. इन नए घटनाक्रमों के मद्देनजर, वर्तमान याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। तदनुसार, राज्य को आवश्यक संशोधन करने और कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए नए सिरे से विज्ञापन देने की अनुमति दी जाती है।

4. अंतिम विज्ञापन की तिथि से आज तक लगभग चार वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों में से जो आगामी विज्ञापन के संदर्भ में अधिक आयु के होने की संभावना रखते हैं, ऐसे उम्मीदवारों (जो दिनांक 08.03.2019 के विज्ञापन के आवेदक हैं) के लिए, ***राज्य सरकार को प्रस्तावित संशोधन में एक***

बार के उपाय के रूप में आयु में छूट देने का प्रावधान करना चाहिए। उपरोक्त अभ्यास इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

5. लंबित आई.ए., यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

6. इस स्तर पर, एक प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित संशोधन को चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जा सकती है। ऐसी स्वतंत्रता इस कारण से आवश्यक नहीं है कि जब भी नियम या संशोधित नियम नए सिरे से जारी किए जाएंगे, तो यह संबंधित पक्षों के लिए कार्रवाई का एक नया कारण होगा।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री राजीव धवन, श्री रंजीत कुमार और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया कि रिट याचिकाकर्ता, विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया में जानबूझकर भाग लेने के कारण, सहमति के सिद्धांत से बंधे थे और इसलिए, पात्रता मानदंड को बाद में चुनौती नहीं दे सकते थे। **पंजाब नेशनल बैंक बनाम अनित कुमार दास** (2021) 12 एससीसी 80 और **चेयरमैन एसबीआई और अन्य बनाम एम.जे. जेम्स** (2022) 2 एससीसी 301 पर भरोसा किया जाता है।

14. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और अंतिम चयन सूची तैयार होने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना अनुचित है और परिणामों की घोषणा के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है, जो अस्वीकार्य है। **के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य** (2008) 3 एससीसी 512 पर भरोसा किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता, जो विज्ञापन के अनुसार चयन की उचित प्रक्रिया के बाद सफल हुए, उन्हें नियुक्त होने का अधिकार है और इसके बजाय उन्हें बिना किसी गलती के पीड़ित किया जा रहा है।

15. उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया निर्णय मनमानी कार्रवाई है क्योंकि यह नियम 9(1)(iii) के साथ चिंता/विसंगति को निर्दिष्ट करने में विफल रहा है जिसके कारण पूरी प्रक्रिया को रद्द करना आवश्यक हो गया।

16. निजी प्रतिवादियों यानी रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया कि इस तरह के विलंबित चरण में पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने से उनके हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एआईसीटीई के रुख के अनुसार, उनके आवेदन योग्य थे और इसलिए अपीलकर्ताओं के आवेदनों के साथ उन पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

17. राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पटवालिया ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पूर्व में लागू नियमों के संबंध में उत्पन्न अनेक कानूनी मुद्दों पर विचार करते हुए चयन प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है कि अपने निर्णयों के अनुसरण में, जैसा कि आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमोदित है, बिहार सरकार ने विद्यमान नियमों को निरस्त कर दिया है तथा अधिसूचना संख्या 1174 दिनांक 07.03.2023 के तहत बिहार अधीनस्थ अभियंत्रण (सिविल/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियम, 2023 (**'नए नियम'**) को अधिसूचित किया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, नए नियमों के नियम 8(2) के अंतर्गत एकमुश्त आयु में छूट प्रदान करने के लिए उचित प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा, बीटीएससी ने दिनांक 10.04.2023 के नोटिस के माध्यम से विज्ञापन को रद्द कर दिया है और जल संसाधन विभाग द्वारा बीटीएससी को उस विभाग में जूनियर इंजीनियरों के 2252 रिक्त पदों के विरुद्ध चयन के लिए दिनांक 21.03.2023 के पत्र के माध्यम से नए अधियाचन भेजे गए हैं।

18. श्री पटवालिया ने आगे तर्क दिया कि विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया को पूरा करना, जिसके परिणामस्वरूप चयन सूची और अंतिम चयन सूची बनी, लगातार इस शर्त के साथ की गई कि नियुक्तियाँ लंबित मुकदमे के परिणाम के अधीन होंगी। उनका तर्क है कि जबकि चयन सूची को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2022 के आदेश के तहत आंशिक रूप से अपास्त किया गया था, अंतिम चयन सूची पर न तो उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और न ही प्रकाशित किया गया, और इसलिए, अपीलकर्ताओं के पास नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, जिससे इक्विटी का कोई दावा अस्थिर हो जाता है।

19. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने दिनांक 24.04.2023 के आदेश के तहत यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था जो आज तक कायम है। राज्य की सबसे हालिया स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जूनियर इंजीनियरों

के लगभग 9,187 पद रिक्त हैं, जिससे राज्य के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर भारी असर पड़ रहा है। चूंकि सेवानिवृत्ति जारी है, इसलिए कार्यरत संख्या लगातार कम हो रही है और वर्तमान में 11.7% है। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, श्री पटवालिया ने इस न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से कहा है कि राज्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी उचित निर्देश का पालन करेगा।

20. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

21. जैसा कि ऊपर साक्ष्य दिया गया है, वर्तमान मामले का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। विज्ञापन जारी होने से पहले, 2017 में नियमों में संशोधन किया गया था, विशेष रूप से नियम 9 में, जिसने पात्रता मानदंड को केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया था, जिनके पास एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा था। यह संशोधन प्रथम दृष्टया **भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर)** में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत था, जो इस न्यायालय के समक्ष एआईसीटीई के रुख और 19.02.2022 की उनकी सार्वजनिक सूचना से पुष्ट होता है। हालांकि, इस उल्लंघन के बावजूद, विज्ञापन में वही प्रतिबंध था, जो रिट याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को चयन प्रक्रिया से मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराता था।

22. इसके बाद, तैयार की गई पहली चयन सूची को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7312/2021 में दिनांक 19.04.2022 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अपास्त किया गया और बीटीएससी को निम्नानुसार एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया:

> *"तदनुसार, संशोधित नियमावली, 2017 के नियम 4(ए) के अंतर्गत की गई नियुक्तियों को रद्द किया जाता है और बिहार राज्य तकनीकी चयन आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी डिप्लोमा धारकों को 40% संस्थागत आरक्षण देते हुए नए सिरे से चयन/मेरिट सूची तैयार करे, जिन्होंने बिहार राज्य के भीतर एआईसीटीयू द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य तकनीकी संस्थान बोर्ड, बिहार, पटना से संबद्ध किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान से अपना डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।"*

23. परिणामस्वरूप, 02.04.2022 को तैयार की गई चयन सूची को निहित रूप से अलग रखा गया था और बीटीएससी द्वारा दिनांक 19.04.2022 के आदेश के अनुपालन में एक अंतिम चयन सूची तैयार की गई थी, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया था, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2022 के आदेश के अनुसार एक अन्य अनुरूप रिट कार्यवाही सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7761/2022 में आदेश दिया गया था:

"...8.9.2019 के विज्ञापन के अनुसार चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है।

इन परिस्थितियों में, जैसा कि प्रार्थना की गई है, हम जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हैं।

इस बीच, चयन की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन परिणाम अदालत की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा।"

24. यह ध्यान देने योग्य है कि 2021 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 7312 में पारित दिनांक 19.04.2022 के आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम रूप ले चुका है। बीटीएससी द्वारा यह कहा गया है कि अंतिम चयन सूची तैयार की गई थी और उसे सीलबंद कवर में रखा गया था। जबकि सूची जारी करने की मांग करने वाला एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, रिट याचिका वापस ले ली गई थी।

25. वर्तमान कार्यवाही के दौरान, दिनांक 10.09.2024 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने राज्य सरकार से अंतिम चयन सूची के संबंध में जानकारी मांगी और उसे सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

26. वर्तमान में, अंतिम चयन सूची तैयार होने के बावजूद, जो नियुक्ति प्रक्रिया के समापन का संकेत देती है, राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया को खत्म करके नए नियमों के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को प्रभावी रूप से बदलने के बराबर है, जो अस्वीकार्य है और उम्मीदवारों को पिछले नियमों के तहत विचार के उनके वैध अधिकार से वंचित करता है।

27. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अचानक और बिना कारण बताए तथा रिट याचिकाओं में शामिल किसी भी मुद्दे पर निर्णय लिए बिना ही उनका निपटारा कर दिया तथा राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान को दर्ज कर लिया तथा राज्य को संबंधित नियमों में संशोधन करने की अनुमति दे दी। चूंकि, 02.04.2022 को चयन सूची घोषित होने तक पूरी भर्ती प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार संपन्न हुई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से रद्द नहीं किया गया है, और चूंकि एआईसीटीई ने भी अपना रुख जारी रखा है कि निजी संस्थानों के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक नहीं है, और चूंकि

सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7312/2021 में पारित दिनांक 19.04.2022 के आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, हमारी राय में, न्याय का हित पूरा होगा यदि राज्य/आयोग को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि पिछले दस वर्षों से अधिक समय से कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है, दिनांक 08.03.2019 के विज्ञापन के संबंध में मेधावी उम्मीदवारों की एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए। अतः यह निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि उपरोक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए तथा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7312/2021 में पारित दिनांक 19.04.2022 के आदेश के अनुपालन में यथाशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश के तीन माह के भीतर दिनांक 08.03.2019 के विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की एक नई चयन सूची तैयार की जाए।

28. इस संबंध में, **के. मंजूश्री** (ऊपर) में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का समर्थन किया गया है, जिसमें न्यायालय ने पिछले निर्णयों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से माना है कि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद चयन प्रक्रिया में नई आवश्यकताओं को शामिल करना खेल के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है। निर्णय के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

> *"**27.** लेकिन जो नहीं किया जा सका वह दूसरा परिवर्तन था, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों का मानदंड प्रस्तुत करना। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड II) के चयन के लिए पहले कभी नहीं अपनाया था। वर्तमान चयन के संबंध में, प्रशासनिक समिति ने केवल प्रचलित पिछली प्रक्रिया को अपनाया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पिछली प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक लागू करने की थी, मौखिक परीक्षा के लिए नहीं। हमने 24-7-2001 और 21-2-2002 के पिछले प्रस्तावों की उचित व्याख्या का उल्लेख किया है और माना है कि 30-11-2004 को जो अपनाया गया था वह केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक थे, साक्षात्कार के लिए नहीं। **इसलिए, संपूर्ण चयन प्रक्रिया (जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं) पूरी हो जाने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता को प्रस्तुत करना, चयन प्रक्रिया में बदलाव के समान होगा।** खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों का उल्लंघन करना स्पष्ट रूप से अनुचित है। इस न्यायालय के कई निर्णयों से हम इस दृष्टिकोण से पुष्ट हैं। उनमें से तीन*

का उल्लेख करना पर्याप्त है - पी.के. रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ [(1984) 2 एससीसी 141: 1984 एससीसी (एल एंड एस) 214], उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ [(1985) 3 एससीसी 721: 1985 एससीसी (एल एंड एस) 919] और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य [(1987) 4 एससीसी 646: 1988 एससीसी (एल एंड एस) 36: (1987) 5 एटीसी 148]

32. महाराष्ट्र एसआरटीसी बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे [(2001) 10 एससीसी 51: 2002 एससीसी (एलएंडएस) 720] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि **"खेल के नियम, जिसका अर्थ है कि चयन के लिए मानदंड संबंधित अधिकारियों द्वारा बीच में या चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता है"। इस मामले में स्थिति बहुत अधिक गंभीर है। यहां, न केवल खेल के नियम बदले गए, बल्कि खेल खेले जाने के बाद और खेल के परिणामों की प्रतीक्षा किए जाने के बाद उन्हें बदला गया। यह अस्वीकार्य और अनुचित है।**

29. इसलिए, उपर्युक्त स्थिति के आलोक में, संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने की राज्य की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों, विशेष रूप से लंबे समय तक लंबित रहने के कारण बड़ी संख्या में रिक्त पद होने से सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है, को देखते हुए, यह न्यायालय राज्य/बीटीएससी के लिए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7312/2021 में दिनांक 19.04.2022 के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत नई चयन सूची के साथ आगे बढ़ना उचित पाता है, जो अंतिम रूप ले चुकी है, साथ ही जहां तक संभव हो, सफल पाए गए उम्मीदवारों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए, नई चयन सूची को निम्नलिखित तरीके से उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए:

(i) सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 7312/2021 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.04.2022 के आदेश को ध्यान में रखते हुए नई चयन सूची तैयार की जाए।

(ii) नई चयन सूची में जहां तक संभव हो वे मेधावी उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो अन्यथा पात्र थे, लेकिन केवल नियमों में 2017 के संशोधन के कारण अपात्र घोषित किए गए थे, यानी उनके संस्थान को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने के कारण और सभी समान रूप से सफल उम्मीदवार।

(iii) बी. टी. एस. सी. को इस आदेश के 3 महीने के भीतर संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है और राज्य सरकार को इसके बाद 30 दिनों

की अवधि के भीतर आयोग द्वारा प्रस्तुत संशोधित चयन सूची पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

30. तदनुसार, वर्तमान अपीलों का निपटारा पूर्व उल्लिखित निर्देशों के साथ किया जाता है।

* लेखक

† द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः अंकित ज्ञान